



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्रसाचारण

27/2

EXTRAORDINARY

भाग II—पार्ट 3—उपलब्ध (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1) १२

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162] नई विलासी, शुक्रवार, अक्टूबर 3, 1969/आस्विन 11, 1891

No. 162] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 3, 1969/ASVINA XI, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या भी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT &
COOPERATION
(Department of Food)
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October 1969

G.S.R. 2366.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ix) of clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 (59 of 1968), the Central Government, being of opinion that strikes in any service in the Food Corporation of India, established under the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), would prejudicially affect the maintenance of supplies and services necessary for the life of the community and would result in the infliction of grave hardship on the community, hereby declares the service in the Food Corporation of India to be an essential service for the purposes of the said Act.

2. This notification shall have effect from the 5th October, 1969

[No. F. 10-25/69-FCC.]

R. BALASUBRAMANIAN, Jt. Secy

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 1969

सं० फा० 2367 —आवश्यक सेवाएँ बनाए रखना अधिनियम, 1968 (1968 का 59) की धारा 2 की उपधारा (1) के खड़ (क) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अपनी यह राय होने के कारण कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) के अधीन स्थापित, फूड कारपोरेशन आफ इंडिया की किसी सेवा में हड्डतालों का जनसमुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उसके परिणाम स्वरूप जनसमुदाय को बड़ी कठिनाइयां होंगी, फूड कारपोरेशन आफ इंडिया की सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एतद्वारा आवश्यक सेवा घोषित करती है।

2. यह अधिसूचना 5 अक्टूबर, 1969 से प्रवृत्त हो जाएगी ।

[सं० फा० 10-25/69-एफ०सी०सी०]

आर० बालसुब्रमण्यन,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।